International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 226-230

औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

सार

किसी भी देश के विकास में औद्योगीकरण प्रक्रिया अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समय–समय पर औद्योगीकरण की दिशा तथा गति को नियन्त्रित एवं नियमित करने, पूँजी विनियोग की मात्रा तथा दिशा को निर्धारित करने और आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उनमें समयानुकुल संशोधन करने के लिए उनके प्रभावों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अतः इन सबके लिए यह आवश्यक है कि औद्योगीकरण से देश की अर्थ–व्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हैं। तीव्र औद्योगीकरण की धुन में आर्थिक विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय विकास तथा मानवीय मूल्य अदि सभी तथ्य उपेक्षित ही रह गये। इसका परिणाम यह हुआ कि एक और जहाँ सुख समृद्धि के ढेर लगे वहीं दूसरी ओर अपार जन–समूह अभावग्रस्त एवं अविकसित ही पड़ा रह गया। मियरडीथ ने इम विषय में लिखा है कि "इस स्थिति के उद्भव में प्रमुख हाथ नवीनतम प्राविधिक गतिविधियों एवं तीव्र औद्योगीकरण से प्राप्त लाभों के विभिन्न जन समूहों में एक न्यायसंगत वितरण व्यवस्था के आधार के अभाव का था। इसलिए हमें सारा औद्योगीकरण सोच–समझ कर और काफी सर्तक रहकर करना है। सेमीकॉन इंडिया प्रोगाम और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी जैसी पहलों से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण मी प्रतिभा विकास के लिए सरकार की 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस यात्रा के केन्द्र में है। राजस्थान भी सेमीकंडक्टर उद्योग में पहचान बना रहा है। भिवाड़ी में सहस सेमीकंडक्टर्स मेमोरी चिप्स का व्यावसायिक उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कम्पनी बन गई है। अधिक निवेश उत्कीर्ण करने के लिए, 2001 में राज्य सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरु की, जो इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। लेकिन प्रदेश को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। खासकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण का समर्थन करने के लिए एक कुशल कार्यबल विकसित करने की। आई टी और सॉफ्टवेयर विकास में स्थानीय प्रतिभा की कमी के कारण राजस्थान को फीसमी को आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

शब्दकोशः *औद्योगीकरण, पूँजी विनियोग, विकेन्द्रीकरण विनिर्माण, पूँजीगत आधार, आर्थिक विकास।*

प्रस्तावना

औद्योगीकरण अल्प–विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की संजीवनी है, क्योंकि इससे ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था से व्यापक रूप से दीर्घकालीन जड़ता या अवरोधक को दूर करके ऐसी हलचल पैदा की जा सकती हैं जो वहाँ के सुसुप्त समाज को झकझोर देती है और उन्हें चिरकालीन निद्रा से जगाकर आर्थिक विकास की

* सह आचार्य ई. ए. एफ. एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

ऊषा बेला में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की प्रेरणा प्रदान करती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि अल्पविकसित देशों में दो तिहाई जनसंख्या आर्थिक विषमताओं की शिकार है। श्री गुन्नार का स्पष्ट मत है कि औद्योगीकरण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का एक माध्यम है। अधिकतम लोगों को रोजगार दिलाने के मानवीय उद्देश्यों और त्रीव आर्थिक विकास के बीच निहित है। कुटीर व लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य रोजगार के सुअवसरों में वृद्धि करना है और वृहद पैमाने के उद्योगों के विकास करने के पीछे मूल लक्ष्य देश का तीव्र औद्योगीकरण होता है। यह सत्य है बडे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता देने से औद्योगिक विकास की गति तीव्र होती है। पूँजी निर्माण की गति बढ़ती है, अवशोषित सधानों का उपयोग और बाजारों का विस्तार होता है बढ़ते हुए उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत विकास की गति तेज होती है, परन्तु व्यापक आर्थिक विषमताएँ, दरिद्रता, बेरोजगारी, निम्न जीवनस्तर, मानवीय मूल्यों का ह्रास, बढ़ती हुई सामाजिक लागत, शोषण और भुखमरी इत्यादि इस तस्वीर का दूसरा पहलू होता है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि आर्थिक विकास का सहारा उत्तरदायित्व लघु एवं कुटीर उद्योगों पर छोड़ा जाता है तो देश का तीव्र औद्योगीकरण नहीं हो सकेगा और न ही निर्धनता के कुचक्र से हमें मुक्त मिलेगी, यद्यपि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने के अवसर और रोजगार की उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध हो जायेगी ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों विकल्पों में से चुनाव के पहलू को स्थगित करते हुए किसी ऐसे विकल्प की खोज की जाये जिससे कि समस्या का वास्तविक हल प्राप्त किया है।

औद्योगीकरण के मूल उद्देश्य

औद्योगीकरण अल्पविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की संजीवनी है, क्योंकि उसने ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था से व्यापक रूप से दीर्घकालीन जड़ता या अवरोधक को दूर करके ऐसी हलचल पैदा की जा सकती है जो वहाँ के सुसुप्त समाज को झकझोर देती है और उन्हें चिरकालीन निद्रा से जगाकर आर्थिक विकास की ऊषा बेला में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सामान्यतया सभी अल्प विकसीत राष्ट्र एक लम्बे समय तक साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आर्थिक शोषण के शिकार रहे हैं। आज भी देश दो गुटों में विभाजित है। विकसित देश औद्योगीकृत है और इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादकता एवं सम्पन्नता वहाँ ज्यादा है। ये देश संख्या में कम होते हुए भी शक्तिशाली है। दूसरी ओर अल्पविकसित देशों की संख्या ज्यादा होते हुए भी वे आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हैं क्योंकि वे औद्योगीकृत नहीं है। उन्नत उत्पादन तकनीक एवं मशीनों व यन्त्रों के इन देशों को आयोगिक रूप से विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। सामरिक क्षमता एवं प्रतिरक्षा क्षमता की दृष्टि से भी अल्प–विकसित देशों की स्थिति अच्छी नहीं है। अल्प विकास विश्व रंगमंच पर इन देशों की निरीह एवं कमजोर स्थिति मुख्य कारण है जिसे दूर करने के के उद्देश्य से ये देश औद्योगीकरण का सहारा लेना चाहते है।

- **पूँजीगत आधार पर उद्योग स्थापित करना** :– औद्योगीकरण में देश के अन्तर्गत मशीनें बनती हैं, विद्युत एवं शक्ति का निर्माण होता है पूँजीगत उद्योग विकसित होते हैं जो देश के भावी आर्थिक विकास की सम्भावनाओं में वृद्धि करते हैं। देश में सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना से तीव्र गति से हुई जनसंख्या को रोजगार मिलता है तथा भूमि पर ये जनसंख्या का बोझ कम हो जाता है।
- **राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना** :– विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण की गति बढ़ती है उसके आर्थिक विषय में मितव्ययिता बढ़ती जाती है। तीव्र औद्योगीकरण से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होने पर बचतें भी बढ़ती है तथा भावी औद्योगीकरण के लिए आवश्यक मात्रा में पूँजी सरलता पूर्वक एकत्रित हो जाती है।
- **उत्पादन विधियों का आधुनिकीकरण** :– औद्योगीकरण की प्रक्रिया देश में मशीनीकरण तथा तकनीकी कार्य–कुशलता का प्रसार करती है, श्रमिकों कार्य क्षमता में वृद्धि करती है तथा जन साधारण के मस्तिष्क में आर्थिक विकास के लिए प्रेरणापद वातावरण का निर्माण करती है। उद्योगों के विकास से

आर्थिक जीवन के अन्य अंग जैसे कृषि, व्यापार परिवहन अधिकोषण, बीमा, वित्त, वाणिज्य तथ सेवाएँ आदि भी विकसित होते हैं और इन सबके विकास से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

- **नवीन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि** :– औद्योगीकरण का तात्पर्य कारखानों, मिलों, खानों, शक्ति के संयन्त्रों, रेलवे आदि निर्माण सम्बन्धी तथा धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित क्रियाओं–विशेषकर वे जिनके माध्यम से आधुनिक बाह्य संरचना का निर्माण व संचालन होता होने के महत्व में पूर्ण एवं सम्बन्धित विकास से है।
- **सन्तुलित अर्थव्यवस्था की स्थापना** :– सन्तुलित औद्योगीकरण के सभी क्षेत्रों में समन्वित विकास होता है तथा देश में उपभोक्ता सामग्री एवं पूँजीगत माल बनाने बाले सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है। दूसरे अविकसित देशों की कृषि प्रदान अर्थव्यवस्था भी औद्योगिक विकास व सन्तुलित होती है और उत्पादन के सभी साधनों का मितव्ययी तथा अधिकतम उपयोग सम्भव होता है।
- **कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए** :– भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। आज भी अधिकांश कृषि कियाएँ परम्परागत आधार पर की जाती हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादिकता बढ़ाने के लिए नवीन कृषि प्रविधियाँ रामायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषियंत्र आवश्यक है। अतः कृषि विकास के लिए औद्योगीकरण का बहुत ही महत्व है। कुछ लोगों की यह विचारधारा है कि औद्योगीकरण एवं कृषि में विरोधाभास है, परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि लोगों पर निर्भर है और उद्योग कृषि पर, अर्थात ये एक–दूसरे के पुरक हैं। बहुत से उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे–सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग आदि दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषियंत्र उद्योगों से कृषि को प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए

अधिकांश अल्पविकसित देशों का भुगतान – सन्तुलन उनके विपक्ष में होता है क्योंकि उन्हें विकसित देशों से बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इन देशों में जो निर्यात किया जाता है वह प्रायः कच्चे माल ही होता है परन्तु औद्योगीकरण के द्वारा हम अपने देश में ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके न केवल देश की आन्तरिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि निर्यात के निर्यात के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करके भुगतान सन्तुलन को अपने पक्ष में कर सकते है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात का महत्व अत्यधिक बढ़ चुका है और हम पूँजीगत वस्तुओं का भी निर्यात करने लगे हैं। निर्यात बढ़ाकर विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाता है जिसमें देश के औधोगीकरण को ओर अधिक गति मिलती है। इस प्रकार औधोगीकरण का व्यापार वृद्धि एवं भुगतान सन्तुलन की दृष्टि है बहुत बड़ा महत्व है।

औद्योगीकरण के प्रभाव

- **आर्थिक संरचना में परिवर्तन** :– औद्योगीकरण के कारण देश के आन्तरिक अर्थिक कलेवर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सर्वप्रथम, जनसंख्या के पेशेवर वितरण के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। प्राथमिक व्यवसायों में जनसंख्या का प्रतिशत कम होकर द्वितीयक व्यवसायों में बढ़ जाता है। नये–नये औधोगिक संस्थानों की स्थापना से फैक्ट्री रोजगार की सम्भावना बढ़ती है। कृषि पर जन भार कम होने लगता है। औद्योगीकरण के कारण आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्योग केवल बड़े–बड़े शहरों में ही स्थापित नहीं होते अपितु उनका प्रसार गाँवों की ओर भी होता है। शहरों में एक नयी औद्योगिक सभ्यता जन्म लेती है और वहाँ रोजगार, श्रम, जन–स्वास्थ्य तथा औधोगिक संरक्षण आदि नयी–नयी समस्याएँ जन्म लेती हैं। उद्योगों की संख्या बढ़ने पर सरकार का भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है तथा उसके सार्वजनिक व्यय, कराधान एवं विनियोग की मात्रा तथा प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। सरकार की सभी नीतियों आवश्यकतानुकूल ढालनी होती है और उसे औद्योगिक केन्द्रों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, परिवहन, बिजली, पानी आदि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करनी होती है।

- **आर्थिक विकास और रोजगार प्रभाव** :– घरेलू निवेश में वृद्धि केवल एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं हैं, बल्कि व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। इसने भारत की जीडीपी वृद्धि रोजगार सृजन और समग्र समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थानीय व्यवसायों और उद्यमियों को सशक्त बनाकर घरेलू निवेश अधिक समावेशी विकास प्रक्षेपक को बढ़ावा दे रहा है। शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाट रहा है। और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बना रहा है। चुनौतियों और आगे का रास्ता सकारात्मक गति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। बुनियादी ढांचे की अड़चने विनियामक जटिलताएं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चिताऐं निरन्तर निवेश वृद्धि में संभावित बाधाएं खड़ी करती है। आगे देखें तो भारत अपनी आर्थिक मात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। घरेलू निवेश में उछाल एक परिवर्तनकारी चरण का संकेत देता है। जहां स्थानीय पूँजी और नवाचार विकास की अगली लहर को आगे बढ़ा रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर भारत में घरेलू निवेश में वृद्धि सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है। बाकि यह निवेश गंतव्य के रूप में देश की लचीलापन और आकर्षण का प्रमाण है। नीतियों बुनियादी ढांचे और उद्यमशीलता की भावना के सही मिश्रण के साथ भारत नए अवसरों को खोलने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से करें ओद्योगिकीकरण

असबैजान में हुए सीओपी 29 जलवायु सम्मेलन का नतीजा निराशा जनक रहा। हमें कुछ हद तक तीन सप्ताह पहले आए अमरीकी चुनाव परिणामों की कुटनीतिक झलक माना जा सकता है। अमरीका के प्रगतिशील राजनीतिक समूह कामकाजी की एवं और श्वेत समुदाय को अपना स्वाभाविक साथी समझते थे, लेकिन इन्हीं वर्गों ने पारंपरिक रिपब्लिकंस के साथ गठजोड़ कर उनके सम्मुख चुनौती पेश कर की। ठीक तरह बाकू में संयुक्त जलवायु सम्मेलन में अमीर देशों के दुनिया में कार्बन उत्तर्जन को कम करने और जलवायु कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के प्रयासों को उन्हीं विकासशील देशों का बहुत कम समर्थन मिल पाया, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के जोखिम से सबसे अधिक जूझ रहे हैं। तेल का फायदा यह है कि तेल क्षेत्र और टर्मिनल दोनों ही अमरीकी डॉलर में कर्ज लेते है। और निर्यात से आय कमाते हैं, जिससे गरीब देश मुद्रा संकटों से बच जाते हैं। अगर किसी ने 2021 में काहिरा के पास एक पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए डॉलर में लगाया होता तो इस साल मिश्र का पाउंड अपनी पिछली कीमत के एक तिहाई तक गिरने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। आपके उपभोक्ताओं की क्षमता इतनी ऊँची बिजली दरें चुकाने की नहीं होती कि आपके ब्याज का भुगतान हो सके। सबसे अच्छा समाधान यह है कि समृद्ध देश यह मानें कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में एक संकट है और उसी के अनुसार कदम उठाएं।

2021 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 650 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकारी जारी किए गए थे। यह एक अस्पष्ट अर्थ–मुद्रा है, जो मुख्य रूप से कन्द्रीय बैंकर्स जानते है और हमने कोविड –19 से हुए नुकसान को कम करने में गरीब देशों की मदद की। इसमें से 69 बिलियन डॉलर संच जलवायु वित्त पोषण के लिए दिए जा रहे हैं। गरीब देशों के लिए बड़े पैमाने पर एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित सौर पैनल, बैटरी और पवन टरबाइन जैसे उपकरण खरीदने में उनकी मदद करे। ये निवेश भले ही बड़ा मुनाफा न दे सकें, लेकिन अगर हर देश स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से औद्योगिकीकरण कर सके और समृद्धि प्राप्त करे तो उसका लाभ पूरी दुनिया को होगा।

औद्योगीकरण आर्थिक विकास की एक व्यापक क्रिया है जो देश के सम्पूर्ण आर्थिक कलेवर में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। औद्योगीकरण का अर्थ राष्ट्र सर्वागीण औद्योगिक विकास से है जिसके फलस्वरूप किसी भी अल्प विकसित देश के ही अर्थव्यवस्था शक्तिशाली, संतुलित तथा आत्म निर्भर बन सके। औद्योगीकरण का क्षेत्र केवल निर्माणी उद्योगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका आशय उत्पादन क्रियाओं में व्यापक परिवर्तन होने से है। ये परिवर्तन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं परन्तु उनमें उद्योगों का यन्त्रीकरण प्रमुख है। यन्त्रीकरण से नये उद्योगों का विकास होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, मूल्य में कमी आती है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु का

बाजार विस्तृत होना है और राष्ट्र में औद्योगीक विकास होता है। औद्योगीकरण एक मशीनी प्रक्रिया मात्र ही नहीं है। यह साधनों के केवल संग्रहमात्र की प्रकिया भी नहीं है। अन्ततः यह एक मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों के समान इसका भी अन्तिम परिणाम उसे संचालित करने वाले मनुष्यों की चतुरता, गुणों एवं दृष्टिकोणों पर ही निर्भर करती है। सामाजिक घटकों के अन्तर्गत समाज में व्याप्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताऐं लोगों की साहसी एवं प्रबन्धकीय क्षमता परस्परागत एवं रूढ़िवादी संस्थाएँ तथा अन्त में जन साधारण का विकास के प्रति दृष्टिकोण आदि तत्व आते हैं। अपरिवर्तित सामाजिक वातावरण में आर्थिक नहीं हो सकता अतः पहले उसमें समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी देश में विकास केवल आर्थिक शक्तियों पर ही निर्भर नहीं करता और कोई देश जितना अविकसित है उतनी ही यह बात सत्य होगी। मनुष्यों के मस्तिष्क, सामाजिक संस्थाएँ विचारों की अभिव्यक्ति तथा विकास अवसरों की उपलब्धि ही आर्थिक विकास की कुंजी है। परन्तु एक अविकसित मौर वह औद्योगीकरण में बाधक तत्वों को सहारा देता है।

निष्कर्ष

भारत के द्रुतगामी सन्तुलित तथा सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण एक निरपेक्ष अनिवार्यता है। आज देश के करोडों नागरिकों को एक सभ्य देश के गौरवपूर्ण नागरिक के बराबर जीवन की सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने, उनका जीवनस्तर उठाने, उन्हें सुखी तथा समृद्ध बनाने, उनके राजनीतिक जीवन में स्थिरता लाने तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा उत्पादन बढ़े। परन्तु उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित वित्तिय तथा तकनीकी साधनों की भारत में कमी है। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है भारत का औद्योगीकरण। देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश के कोने–कोने में उद्योगों का जाल बिछ जाये। यदि ऐसा सम्भव न हो सका तो पंचवर्षीय योजनाओं का इतना भारी अनुष्ठान व्यर्थ ही सिद्ध होगा। परन्तु तीव्र औद्योगीकरण के पीछे हमें अन्धे होकर नहीं भागना है। तीव्र औद्योगीकरण से उत्पन होने वाले शेषों को भी ध्यानान्तर्गत रखना पड़ेगा। प्रायः तीव्र औद्योगीकरण वे आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानता आ जाती है, क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो जाता है। तथा कृषि एवं अन्य सेवा उद्योग उपेक्षित रह जाते है। विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक उत्थान में औद्योगीकरण का प्रमुख हाथ होता है। अर्द्ध–विकसित तथा सुविकसित देशों के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में जो आश्चर्यजनक अन्तर पाया जाता है उसका एक प्रमुख कारण सुविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का उद्योग–प्रधान होना है। औद्योगीकरण के विस्तार से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सन्तुलन तथा स्थिरता आती है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सीमा तक तथा मितव्ययिता पूर्ण विदोहन सम्भव होता है। औद्योगीकरण से देश के अन्तर्गत मशीनें बनती है, विद्युत एवं शक्ति का निर्माण होता है, पूँजीगत आधारभूत उद्योग विकसित होते हैं जो देश के भावी आर्थिक विकास की सम्भावनाओं में वृद्धि करते हैं। देश में सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो तीव्र गति से हुई जनसंख्या को रोजगार मिलता है तथा भूमि पर ये जनसंख्या को बोझ कम हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. औद्योगिक अर्थशास्त्र : संजय प्रकाशन जयपुर
2. अन्तर्रानीय व्यापार, विपणन और सार्वजनिक अर्थशास्त्र : लक्ष्मीनारायण नाथूराम,
3. डॉ. एन.सी. पहाड़ियाँ
4. आर्थिक पर्यावरण भारत में : डॉ आर. सी. जाट, डॉ पी. सी. भिण्डा
5. विक्कीपीडिया, नेट
6. अर्थशास्त्र विशेषांक : 2024 प्रतियोगिता दर्पण
7. दैनिक नवज्योति संपादकीय 22–7–2024
8. राजस्थान पत्रिका 30–11–2024
9. दैनिक भास्कर 22–10–2024

❖◆❖